EDITORIAL

The Turn of the Century

The Telecom services came into existence in eighteenth century under the British rule. After a long Journey it was managed through a Govt Telegraphs department. After independence this department was controlled by the communication Ministry with a concept of public utility service and with the ethical approach of service before self and day and night at your duty. The Govt run the P&T department of other welfare and development of the society. The postal wing almost running in loss but after Technological development Telecom wing was earning huge profits. It was the connecting India in real sense even the priority was given to deliver the lowest price of post Card and inland letter and it was treated as priority mail. After a long run of about 150 years the department of P&T was divided in two parts but ministrial Control continued as ministry of communications. At the eve of entry in twenty first century – Late Rajeev Gandhi, The then Prime Minister of India brought a big revolution in Telecom Sector and electro mechanical switching system converted into electronic devices and latter digital Technology. At the end of the twentieth century, a new concept of world economy was launched under the leadership of USA and the then Prime Minister of India Shri Narsimaha Rao advocated and implemented the global policy of capitalist corporate, the liberalisation and privatisation, under this concept. The national and international corporates started putting pressure upon the Govt to allow the private Telecos in the sector and ultimately the door of the Telecom Sector was opened for Private operators after 1994 in India.

The Private operators came in the sector with pager services CDMA and GSM services. They did not enter in Land line services of Telephone and at other hand the department of Telecom spreaded services throughout the country even in every block and Panchayats level.

The Private operators were not competing with the DOT services as they wanted to earn huge profits from the services at the other side DOT's cheap and affordable services were being provided to the people in urban subscriber and rural area by the Govt Telecom Department (DOT). Taking a section of politicians in their side private Telecos started mentioning pressure upon the Govt to convert the DOT, DTS into a corporation.

The new Telecom Policy was drafted by DOT and it was approved by the union Cabinet in the year 1999 in name of completing the target of NTP -1999. The Govt in centre declared to Corporatise the DOT & DTS and after all opposition from the workers the new entity came into existence from 1st October 2000, in name of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL). Since the time of formation of this company some big bosses in DOT were totally against the BSNL and on their initiation the company was treated step motherly by the Govt. The Govt formed this company to provide the level playing game with the private operators but restricted its entry in Mobile sector. only. Through court the BSNL got entry into mobile services and touched first position among all upto 2005 with a big profit upto ten thousand crore. The Company was running in profit up to 2009 and after that it become loss making due to various policies of the Govt. Even though company financial position was not so bad and it again came in operational profit in 2014-15. After entry of Reliance Jio in the sector a drastic fall in revenue was faced not only by BSNL but all the private Telecos also fallen in financial crisis.

It was the time when the top level management as well as the Govt spokesman searched the reason of declining the BSNL and repeatedly used to tell that the huge number of staff are the main reason of loss of the company. The workers fought continuously for revival of BSNL and ultimately to cut the size of staff VRS 2019 was implemented to reduce the staff. A great panic and fear was created among the workers and in one stroke 78569 employees Executive and non-executive opted for VRS.

Now total management is fully busy to complete the process of VRS and other issues of revival are almost lagging behind. It is apprehended the BSNL may face the same situation as it was faced by the MNTL which sinked even after implementation of VRS twice before VRS 2019. A large member of 78569 staff will be retired through VRS on 31-01-2020 and a big vacuum will come. Even a minimum required staff will not remain to maintain the services. The management adopted the policy

of out sourcing but it will take a long time to finalise and to start the maintenance and development works. In between our leased lines, data services MPLS, VPN and other important services through which BSNL is getting very good revenue will be hampered badly.

Every decision is taken unilaterally by the management and no union/association is called to discuss the issue of further road map.

As per our view the VRS optees and retired staff may call for to opt to work and selected staff may redeployed for immediate need of maintenance work without any middle man. The out sourced workers cannot understand our network immediately and it will not be fruit full for the Company. Thus the company which was providing jobs to educated and semi educated younger's of the country has abolished the 78569 jobs in one stroke and the history of the Telecom services with permanent Govt job loss to workers, now turning towards the out sourcing based job where exploitation of workers with less salary and without service condition will be faced. Thus a golden century is turning towards the dark day of working class of eighteenth century.

संपादकीय

दूरसंचार सेवायें – युगपरिवर्तन

दूरसंचार सेवा की शुरूआत अंग्रेजी शासन काल में हुई थी। आजादी के बाद संचार मंत्रालय के अधिन डाक–तार विभाग जन उपयोगिता एवं सामाजिक उत्थान के सिद्धान्त पर चलाती थी। डाक सेवा से हानि उठानी पड़ती थी, फिर भी पोस्टकार्ड जैसे संचार सुविधा को प्राथमिकता दी जाती थी। दूरसंचार सेवा लाभ जनित थे और तकनीकी उत्थान के बाद यह और लाभ जनित हो गया। पूर्व में हस्तचालित दूरसंचार सेवाएं संचालित थी जो कलान्तर में इलेक्ट्रो–मेकेनिकल–स्वीचिगड़ के द्वारा स्वचालित बनाई गई। इस अवधि में टेलीकाम से भारी लाभ होते थे। दूरसंचार एवं डाक सेवाएं भारतीय जनमानस को जोड़ने का वास्तविक श्रोत थे। कलान्तर में डाक एवं तार विभाग को अलग किया गया परन्तु संचार मंत्रालय के नियंत्रण में ही रखा गया। दूरसंचार विभाग अलग होकर काफी विकसित हुई और नबे के दशक में तथा 21वीं शताब्दी में प्रवेश के पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी द्वारा संचार क्रान्ति की योजना के उपरान्त दूरसंचर विभाग ने गुणात्मक विकास किया। पुराने स्वचालित पद्धति का तकनीकी परिवर्तन इलेक्ट्रोनिक उपकरणों द्वारा किया गया जो आगे चल कर डीजीटल तकनीक के रूप में विकसित हुई। दूरसंचार सेवाएं नगर, उपनगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गई। श्री गांधी के निधन के उपरान्त श्री नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। उनके काल में ही अमेरिकी पूंजीवाद द्वारा उत्पादित वैश्विक उदारीकरण एवं निजीकरण के दौर में देश ने करवट बदला। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में देशी–विदेशी निगमित घरानों तथा धन्नासेठ प्रवेश करने के लिए सरकार पर दवाब बनाने लगे। राजनीति के क्षेत्र में अमेरिका परस्त तत्वों ने इसे बढ़ावा दिया तथा सन् 1990 के उपरन्त दूरसंचार क्षेत्र में निजी कम्पनियों का प्रवेश हुआ। ये कम्पनियां जन आकांक्षा के अनुरूप सस्ती सेवा नहीं देना चाहती की क्योंकि मुनाफा कमाना इनका उद्देश्य होता है। उन्होंने समान अवसर के नाम पर दूरसंचार विभाग को निगम में परिवर्तन की जोरदार वकालत शुरू की। सत्ता के गलियोर में बैठे कुछ लोग इसमें शरीक हो गये तथा 1999 में लाये गये नयी दूरसंचार नीति को सफल बनाने के नाम पर पहली अक्टूबर 2000 से दूरसंचार विभाग को निगम में परिवर्तित कर दिया गया। सरकार द्वारा दिये गये वचनबद्धता के मद्देनजर तीस लाख पचहत्तर हजार अधिकारी एवं कर्मचारी निगम में समाहित हो गए। निगम बनने के आरम्भिक दिनों से ही दूरसंचार विभाग में जड़ जमाये कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी भारत संचार निगम की जड़े कमजोर करते रहे और निजी कम्पनियों के हित में नीतियों का निर्धारण कराने में भूमिका निभाते रहे।

आरम्भ में बीएसएनएल को मोबाईल सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई। न्यायालय के द्वारा मोबाइल सेवा में बीएसएनएल को सन् 2002 में प्रवेश मिला। निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के कारण सन् 2005 तक बीएसएनएल सबसे बड़ी उपभोक्ता संख्या वाली कम्पनी के रूप में उभर कर इस क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आ गई। साथ ही 2004–2005 में दस हजार करोड़ से उपर की राशि का मुनाफा अर्जित किया।

सन् 2009 तक कम्पनी बिना किसी सरकारी सहायता के लाभ में रही परन्तु सरकार की निजी कम्पनियों की ओर झुकाव ने कम्पनी को घाटे में गिरने को मजबूर किया। अपने लगन और मेहनत से कामगारों ने फिर वर्ष 2013–2014 से तीन वर्षों तक कम्पनी का परिचालन लाभ की स्थिति में उठाकर लाया परन्तु सितम्बर 2016 में रिलायन्स जियो के इस क्षेत्र में प्रवेश के बाद बीएसएनएल सहित सभी निजी कम्पनियों की आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई। कर्मचारी बीएसएनएल के पुनरूथान के लिए लगातार संघर्ष करते रहे परन्तु सरकार चुपी साधे रही। हर मोर्चे पर सरकार के लोग कहने लगे कि बीएसएनएल में मौजूद कर्मचारियों की अधिक संख्या के कारण कम्पनी का उत्थान संभव नहीं है और अन्ततः रिवाइवल प्लान के नाम पर बीआरएस 2019 लाया गया। कम्पनी में बड़े सोचे समझे नीति के तहत भ्रम एवं भय की स्थिति पैदा

की गई। कर्मचारियों के बीच दहशतगर्दी पैदा की गई और भ्रम एवं भय के झौके मे बहकर 78569 कर्मचारियों ने वीआरएस के माध्यम से सेवानिवृति का विकल्प दे दिया।

नववर्ष 2020 के प्रथम दिवस को ही एक बड़ा शून्य उत्पन्न होने वाला है। अनुरक्षण एवं विकास मे लगे कर्मचारियों के अभाव में एकाएक कार्य ठप पड़ जायेंगे पर आगे संचालन का कोई प्रारूप नहीं तैयार किया जा सका है।

बीएसएनएल प्रबंधन ने आउटसोर्सिंग की नीति को अपनाया है। यह तत्कालिक प्रभाव से संभव नहीं है। इस बीच हमने सलाह दिये हैं कि वीआरएस पर जाने वाले कर्मियों से ही आप्सन के आधार पर चयन कर कार्य पर रखे जाए ताकि सेवाएं ठप होने से बचाय जा सके। समय की पुकार है कि वीआरएस के बाद बचे हुए कर्मचारी/अधिकारी एकजुट होकर आगे का कार्य प्रारूप तैयार करें अन्यथा एमटीएनएल में पूर्व में हुए दो वीआरएस के बाद का अनुभव मालूम है, कि एमटीएनएल की दशा सुधारने के बजाय बिगड़ते गयी। यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि मजदूरों द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व जो कल्यानात्मक अधिकार हासिल हुए थे सब समापन की दौर में है।

जहां डीओटी/बीएसएनएल में हर वर्ष भर्त्ती होती थी, वहीं अठहत्तर हजार पांच सौ उनहत्तर नौकरियां एक झटके में समाप्त कर दी गई और आउट सौर्सिंग पर लाये गये कर्मचारी/मजदूर शोषण के शिकार होंगे जहां उनके काम के घंटे और वेतन का कोई वाजिब निर्धारण की व्यवस्था नहीं होगी। सह युगपरिवर्तन एवं इतिहास परिवर्तन ही तो है। आइये हम मिलकर फिर से अपने हकों के रक्षार्थ गोलबंद हों।